संख्या:72/2024/155/35-4-2024/35-4099/40/2022

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
एटा।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक: 21 फरवरी, 2024

विषय: जनपद एटा में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या- 01/2021/01/35-4-2021, दिनांक 04 जनवरी, 2021 द्वारा जनपद-एटा की विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के ग्राम कलिंजर में राजकीय आई०टी०आई० के भवन निर्माण कार्य हेतु रू0 1103.22 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रु0 275.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-21/2023/29/35-4-2023/001-35-4099/40/2022, दिनांक 05 जनवरी, 2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 275.81 लाख एवं शासनादेश सं0-680/2023/1606/35-4-2023/35-4099/58/2023, दिनांक 22 जून, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में 275.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू.827.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी द्वारा पत्र सं0-2601/2ए, दिनांक 08 नवम्बर, 2023 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग एवं धनराशि रू0 01.19 लाख की बचत को इंगित करते हुए रू0 274.60 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि एवं बचत धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में जनपद की मांग के अनुरूप रु0 274.60 लाख (रुपये दो करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	बचत की धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के ग्राम कलींजर में राजकीय आई0टी0 आई0 का भवन निर्माण कार्य	1103.22	827.43	1.19	274.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.जनवरी,2021, दिनांक 05.01.2023 एवं दिनांक 22 जून, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/ अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग- 4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 2,74,60,000/- (रुपये दो करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 4250002030302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण के चालू कार्य के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:72/2024/155(1)/35-4-2024/35-4099/40/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मण्डलायुक्त, अलीगढ मण्डल।
8. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग, उ०प्र०।
10. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. मुख्य विकास अधिकारी, एटा।
12. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, एटा।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, एटा।
15. सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।